17 OCT 6 2026.qxd 16-10-2026 19:25 Page 1



## संसदका विशेष सत्र

केन्द्र सरकार अब संसदका विशेष सत्र बुलानेकी तैयारीमें जुट गयी है। ऐसे संकेत मिले हैं कि अक्तूबरके अन्तिम सप्ताहमें यह सत्र बुलाया जा रहा है। संसदका मानसून सत्र १३ अगस्तको समाप्त हुआ था लेकिन अबतक सत्रावसान नहीं हुआ है। सत्र बुलानेकी सूचना एक सप्ताह पहले ही देनेकी परम्परा है। लोकसभा सीटें बढ़ाने और परिसीमन बिलसे सम्बन्धित बिल पेश करनेका अनुमान है। इसके माध्यमसे महिला आरक्षण लागू किया जायगा। संविधान (१३१वां संशोधन) विधेयक, २०२६ में लोकसभाकी सीटें ८५० करनेका प्रस्ताव है। राज्योंसे ८१५ और केन्द्रशासित प्रदेशसे ३५ सीटें हो सकती हैं। इसके साथ ही परिसीमन (संशोधन) विधेयक, २०२६ भी पेश किया जा सकता है। परिसीमनके लिए 'जनसंख्या' की परिभाषामें परिवर्तन किया जायगा। २०११ की जनगणनाको आधार बनाया जायगा। इसके अतिरिक्त केन्द्रशासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, २०२६ भी है। यह विधेयक पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू-कश्मीरके कानूनोंमें संशोधन करता है, ताकि परिसीमन और महिला आरक्षण बिल लागू हो सके। भाजपाके नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन (राजग) के पक्षमें दो-तिहाई बहुमत आवश्यक है लेकिन राजग अभी इससे दूर है। लोकसभामें २० और राज्यसभामें नौ सांसदोंकी जरूरत है। लोकसभामें ५४३ सांसद हैं। तीन सीटें खाली हैं। इनमें राजगके ३१८ सांसद हैं। बिलको पास करानेके लिए लोकसभामें ३६० वोटकी आवश्यकता है। यदि द्रमुकके २२ सांसद बिलका समर्थन करते हैं तो बिलके समर्थनमें ३४० सांसद हो जायंगे। इसके बाद भी भाजपाको लगभग बीस सांसदोंकी जरूरत है। इसी प्रकार राज्यसभामें २४५ सीटें हैं। तीन खाली हैं। इनमें राजगके १५३ सांसद हैं। बिल पास करानेके लिए १६२ सांसद चाहिए। राजगको छोटी पार्टियोंके नौ सांसदोंकी जरूरत पड़ेगी। मानसून सत्रकी अन्तिम बैठक १३ अगस्तको हुई थी। दोनों सदनोंकी बिना सत्रावसानके यह अबतककी सबसे लम्बी अवधि है। इसके पूर्व १९८९ में दोनों सदन ६३ दिनतक ऐसी ही स्थितिमें रहे। संसदके विशेष सत्र बुलानेकी तैयारीको लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गयी है। विपक्ष इसे हंगामे वाला सत्र बनानेकी तैयारीमें है। विशेष सत्र ऐसे समय हो रहा है जब मतदाता सूचीके विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमारके इस्तीफेकी मांगपर देशभरमें माहौल काफी गर्म है। संसद सत्रमें इस प्रकरणको भी विपक्ष अवश्य उठा सकता है। विपक्ष और भी कई मुद्दे उठानेकी रणनीति बना रहा है। सत्ता पक्षकी ओरसे भी पूरी तैयारी की जा रही है। सत्तापक्ष यदि दो-तिहाई बहुमत जुटानेमें सफल रहता है तभी बिल पास हो पायंगे।

## अवैध पटाखोंका कारोबार

उत्तर प्रदेशके वाराणसीमें सारनाथ क्षेत्रके पैगम्बरपुरमें गुरुवारको अवैध रूपसे पटाखा बनानेके दौरान हुए भीषण विस्फोटमें तीन मंजिला मकान पूरी तरह ढह गया। इस हादसेमें पटाखा कारोबारी मकान मालिककी ३८ वर्षीय पत्नी गम्भीर रूपसे झुलस गयी जबकि उसका १३ वर्षीय पुत्र मलबेमें दबनेसे घायल हो गया। दोनोंको मण्डलीय अस्पतालमें भर्ती कराया गया है। यह मकान पटाखा कारोबारी राजू खानकी पुस्तैनी है, जहां वह अपनी मां, पत्नी और एक पुत्र और पुत्रीके साथ रहता था। इस मकानमें कई पुश्तसे पटाखा बनानेका अवैध धंधा चल रहा था जिसकी जानकारी आसपासके लोगोंको बखूबी थी लेकिन पुलिस शायद अनभिज्ञ थी या अनभिज्ञ बनी हुई थी, यह तो जांचका विषय है लेकिन इतना तो तय है कि ऐसा हो नहीं सकता कि किसी थाना क्षेत्रमें अवैध कारोबार पुश्तोंसे हो रहा हो और स्थानीय पुलिसको इसकी खबरतक न हो। मकानमें विस्फोट शाम पांच बजे हुआ लेकिन जबतक लोग कुछ समझ पाते तबतक लगातार दो और धमाके हुए जिससे अफरा-तफरी मच गयी। विस्फोटकी भयंकरताका अनुमान इसीसे लगाया जा सकता है कि इस मकानसे सटे एक घरका अगला हिस्सा ढह गया और सात मकान क्षतिग्रस्त हो गये। हादसेके बाद मकान मालिक घायलोंको छोड़कर फरार हो गया जिसे देर रात सारनाथ पुलिसने सरायमोहना घाटके पाससे मुठभेड़के बाद गिरफ्तार कर लिया। घायलोंको लोगोंने मलबेसे निकालकर अस्पताल पहुंचाया। मलबेमें किसी औरके दबे होनेकी आशंकासे पुलिसने दो घण्टे रेस्क्यू अभियान चलाया। राहतकी बात यह है कि और किसीके दबे होनेकी आशंका निर्मूल साबित हुई। पटाखोंका त्योहार दशहरा और दीपावलीके साथ शादी-विवाहकी तैयारियां भी जोरोंपर है। ऐसेमें अवैध पटाखोंकी निर्माणमें तेजी आयी है। गली-गलीमें अवैध तरीकोंसे पटाखोंका निर्माण हो रहा है। इस तरहकी अवैध पटाखोंका निर्माण उत्तर प्रदेशमें नहीं अन्य राज्योंमें भी हो रहा होगा जिसपर सख्त निगरानी रखनेकी जरूरत है वरना ऐसे और भी हादसोंसे इनकार नहीं किया जा सकता है। पुलिस प्रशासनको चुस्त और निगरानी तंत्रको और मजबूत करना होगा, ताकि हादसेकी पुनरावृत्ति रोका जा सके।

## लोक संवाद

### देशमें बढ़ती महंगी

महोदय,-देशमें थोक महंगी फिर तेजीसे बढ़ी है। सितंबरमें थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित महंगी दर बढ़कर ११.३९ फीसदीपर पहुंच गयी। अगस्तमें यह ९.९२ फीसदी थी। सरकारी आंकड़ोंके मुताबिक, यह २०२२-२३ की नयी श्रृंखलामें अबतकका सबसे ऊंचा स्तर है। खाने-पीनेकी चीजों, ईंधन और कारखानोंमें बनने वाले सामानकी कीमतें बढ़नेसे थोक महंगीमें यह तेजी आयी है। सितंबरमें सभी वस्तुओंका थोक मूल्य सूचकांक भी अगस्तके ११०.८ से बढ़कर ११२.५ हो गया। सितंबरमें खाद्य महंगी दर बढ़कर ८.१४ फीसदीपर पहुंच गयी, जो पिछले २१ महीनेका सबसे ऊंचा स्तर है। अगस्तमें यह ५.६७ फीसदी थी। वहीं, प्राथमिक वस्तुओंकी महंगी दर अगस्तके ७.७६ फीसदीसे बढ़कर सितंबरमें ८.६७ फीसदी हो गयी। यह भी नयी श्रृंखलाका सबसे ऊंचा स्तर है। खनिजोंकी महंगी दर ८.२४ फीसदीसे बढ़कर ९.५१ फीसदी हो गयी। थोक महंगी बढ़नेकी एक बड़ी वजह कच्चे तेल और प्राकृतिक गैसकी कीमतोंमें तेजी रही। सितंबरमें ईंधन और बिजलीकी महंगी दर बढ़कर २५.८५ फीसदी हो गयी। अगस्तमें यह २२.९३ फीसदी थी। सबसे ज्यादा तेजी कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसकी कीमतोंमें देखनेको मिली। इनकी महंगी दर अगस्तके ३४.४१ फीसदीसे बढ़कर सितंबरमें ५७.३२ फीसदी हो गयी। इसी तरह कोयले और लिग्नाइटकी महंगी दर १.५७ फीसदीसे बढ़कर ९.३१ फीसदी पहुंच गयी। खनिज तेलकी महंगी दर भी ३८.४८ फीसदीसे बढ़कर ४०.०२ फीसदी हो गयी। सितंबरमें कारखानोंमें बनने वाले सामानकी महंगी दर बढ़कर ९.७६ फीसदी हो गयी, जबकि अगस्तमें यह ८.३७ फीसदी थी। यह भी नयी श्रृंखलाका सबसे ऊंचा स्तर है। थोक महंगी सूचकांकमें इस श्रेणीकी हिस्सेदारी ६३.१ फीसदी है। इसलिए इसकी कीमतोंमें बदलावका कुल थोक महंगीपर बड़ा असर पड़ता है। कपड़े, तैयार परिधान, रसायन, धातुओं और बिजलीके उपकरणोंकी कीमतोंमें वृद्धि दर्ज की गयी। इसके अलावा कम्प्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादोंकी महंगी दर बढ़कर चार फीसदी हो गयी। इससे पहले कई महीनोंतक इस श्रेणीमें कीमतोंमें गिरावट दर्ज की जा रही थी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालयने सितंबरके लिए उत्पादक मूल्य सूचकांक (पीपीआई) के आंकड़े भी जारी किये हैं। यह सूचकांक बताता है कि उत्पादकोंको अपने सामानके लिए मिलने वाली कीमतोंमें कितना बदलाव हुआ है। पीपीआई बढ़कर ११२.५ हो गया। इसके साथ ही पीपीआईपर आधारित महंगी दर अगस्तके ९.८१ फीसदीसे बढ़कर ११.३९ फीसदी पहुंच गयी। सितंबरके आंकड़ोंसे साफ है कि महंगीका दबाव सिर्फ खाने-पीनेकी चीजोंतक सीमित नहीं है। ईंधन, कच्चे माल और कारखानोंमें बनने वाले सामानकी कीमतें भी तेजीसे बढ़ रही हैं। इससे कम्पनियोंकी उत्पादन लागत बढ़ सकती है। यदि कम्पनियां बढ़ी हुई लागतका बोझ ग्राहकोंपर डालती हैं तो आने वाले समयमें खुदरा कीमतोंपर भी दबाव पड़ सकता है। **-शैलजा पाठक, वाया ईमेल।**

# भारतीय प्रतिभाओंपर अमेरिकी निर्भरता

**ट्रम्प प्रशासनने स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रमके तहत विदेशी कामगारोंके लिए वीजापर रोक लगानेकी घोषणा कर दी। यह ऐसा कदम है, जिसका प्रभाव शीर्ष अमेरिकी प्रौद्योगिकी कम्पनियोंके साथ प्रमुख भारतीय आउटसोर्सिंग कम्पनियोंपर भी पड़ेगा। दलील है कि प्रौद्योगिकी उद्योग श्रम कार्यक्रमका दुरुपयोग करता है।**

❐ दिनेश सिंह

हालमें ट्रम्प प्रशासनने स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रमके तहत विदेशी कामगारोंके लिए वीजापर रोक लगानेकी घोषणापर दलील दी है कि प्रौद्योगिकी उद्योग अमेरिकी कामगारोंको कामपर रखनेसे बचनेके लिए रोजगार-आधारित श्रम कार्यक्रमका दुरुपयोग करता है। नये प्रतिबंधोंसे बड़ी संख्यामें भारतीयों सहित सभी विदेशी प्रौद्योगिकी कामगारोंकी नियुक्तिपर प्रतिकूल प्रभाव पड़नेकी सम्भावना है, जिन्होंने ग्रीन कार्ड और अंततः नागरिकता अर्जित करनेके लिए एच१बी वीजाका उपयोग किया था। एकके बाद एक आये अमेरिकी राष्ट्रपतियोंने घरेलू राजनीतिक उद्देश्योंके लिए एच१बी वीजा कोटाको लटकाये रखा। वर्ष २००८ में राष्ट्रपति ओबामाने विदेशोंसे आउटसोर्सिंग करवाने वाली कम्पनियोंके लिए कर छूट समाप्त करनेकी घोषणा की थी। बादमें जो बाइडेनने भी ऐसा ही किया। अमेरिकी प्रौद्योगिकी कम्पनियोंने सस्ते श्रमकी उपलब्धताका लाभ उठानेपर ज्यादा ध्यान दिया। सन् १९६० के दशक में, उन्होंने सेमीकंडक्टर विनिर्माणके साथ ऐसा किया, जो उस समय भारी श्रम-साध्य कार्य था। कालांतरमें उन्होंने सॉफ्टवेयर सेवाओं और प्रोग्रामिंगके मामलेमें यही किया। फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर के अध्यक्ष रॉबर्ट नॉयसने विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करनेके उद्देश्यसे १९६० के दशकमें भारत आदि देशोंका दौरा किया। भारतने इनकार किया तो वे हांगकांग चले गये। नॉयसने कुछ साल बाद इंटेलकी स्थापना की। अन्य अमेरिकी कम्पनियोंने इलेक्ट्रॉनिक्स और इंटीग्रेटेड सर्किट विनिर्माणके लिए सिंगापुर, मलयेशिया और ताइवानको चुना, जिससे ये देश अगले दो दशकोंमें प्रौद्योगिकी विनिर्माणके केन्द्र बन गये। भारतने १९७० और १९८० के दशकमें मौका संभालते हुए अमेरिकी ग्राहकोंके लिए सेमीकंडक्टर डिजाइनए सॉफ्टवेयर सेवाओं और प्रोग्रामिंगमें काम करना शुरू किया।



**भारतीय कम्पनियोंने शुरुआत सेवा निर्यात और आउटसोर्सिंगसे की थी, क्योंकि प्रौद्योगिकी उत्पादों और सेवाओंके लिए कोई घरेलू बाजार नहीं था। न ही ऐसा कोई पारिस्थितिकी तंत्र था जो स्थानीय प्रौद्योगिकी और उत्पाद विकासमें मददगार हो। पिछले दो दशकोंमें बदल गया है। नवाचारके लिए बड़ा स्थानीय बाजार और सहायता प्रणालियां हैं, जैसे उद्यम पूंजीतक पहुंच। जैसे-जैसे यह आगे बढ़ेगा और भारतीय बाजार परिपक्व होगा, आउटसोर्सिंगपर निर्भरता और इससे जुड़ी अनिश्चितताएं कम होती जायेंगी।**

अमेरिकी प्रौद्योगिकी उद्योगके साथ भारतका जुड़ाव कई पड़ावोंसे गुजरा है। इसकी शुरुआत छोटे पैमानेपर 'बॉडी शॉपिंग' से हुई, जिसमें भारतीय इंजीनियर अमेरिकी ग्राहकोंके लिए अल्पकालीन अनुबंधके आधारपर काम करते थे। वे काम पूरा होनेके बाद लौट आते थे। अगले चरणमें, यह एक ऑनसाइट मॉडलके रूपमें विकसित हुआ, जिसमें भारतीय कम्पनियोंने अपने उन श्रमिकोंको भेजा, जो दीर्घकालिक परियोजनाओंपर काम करते हुए अमेरिकी कम्पनियोंके कार्यबलका हिस्सा बने। जैसे-जैसे भारतीय कम्पनियोंने अपने ग्राहकोंका विश्वास हासिल किया और संचार प्रणालीके बुनियादी ढांचेमें सुधार हुआ, इस ऑनसाइट कामका कुछ हिस्सा भारतसे ऑफशोर मॉडलके रूपमें निष्पादित होना शुरू हो गया। जल्द ही अमेरिकी कम्पनियोंको अहसास हुआ कि अमेरिकामें भारतीयोंको बुलाकर कामपर रखने और भारतीय कम्पनियोंपर निर्भर रहनेके बजाय, क्यों न वे सीधे खुद भारतीयोंको कामपर रखें और भारतमें परिचालन स्थापित करें। यह और भी किफायती था। वर्ष १९९० के दशकके अंतमें माइक्रोसॉफ्टने शुरुआत की और कई अन्य तकनीकी कम्पनियोंने इसका अनुसरण किया। फिर बैंकों, बीमाकर्ताओं, लॉजिस्टिक्स कम्पनियों, एयरलाइंस, कानूनी फर्मों, वैश्विक परामर्श और ऑडिटिंग दिग्गजों तथा अन्य कम्पनियोंने भी ऐसा ही किया। आज वे सभी अपने अधिकांश बैकरूम संचालन या व्यावसायिक प्रक्रियाओंको बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, नोएडा आदिमें स्थानांतरित कर चुके हैं।

पिछले दो दशकोंमें इंजीनियरिंग, अनुसंधान एवं विकास और उत्पाद विकासकी आउटसोर्सिंगके साथ-साथ आउटसोर्सिंग व्यवसाय और अधिक विविध होता गया। बड़े निगमोंने अपने कुछ मुख्य कार्योंको संभालनेके लिए भारतमें समर्पित इकाइयां स्थापित कीं। यह बदलाव लागत-बचतसे हटकर नवाचार, अनुसंधान और आईपी (बौद्धिक संपदा) निर्माणकी ओर बढ़ रहा था। आज लगभग हर फॉर्च्यून-५०० कम्पनीका बेंगलुरु या हैदराबादमें पूर्ण स्वामित्व वाला वैश्विक क्षमता केन्द्र (जीसीसी) है। वर्ष २०२५ में ऐसे केन्द्रोंकी संख्या २१०० से अधिक थी, जिनमें २३ लाख ६० हजार लोगोंको रोजगार मिला हुआ है। इससे लगभग सौ बिलियन अमेरिकी डालरका कारोबार होता है। प्रत्येक तकनीकी परिवर्तनमें मेनफ्रेमसे लेकर मिनी और माइक्रो कम्प्यूटर, इंटरनेट और डॉटकॉम, वाई२के, मोबाइल एवं सोशल मीडिया, क्लाउड और बिग डेटातक भारतीय प्रौद्योगिकी कम्पनियोंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब वे एजेंटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) रोलआउट और विभिन्न क्षेत्रोंमें गहन तकनीकी तैनातीके क्षेत्रमें भी यही कर रही हैं तो प्रौद्योगिकी आउटसोर्सिंगकी प्रक्रिया अमेरिका और भारतमें गहराईसे जुड़ी है और अपरिवर्तनीय है। बड़ी तकनीकी कम्पनियोंको तेजीसे रोलआउट, वैश्विक सहायता, विस्तार और अन्य लाभोंके लिए भारतीय इंजीनियरों और तकनीकी प्रतिभाकी आवश्यकता है। वहीं, भारतीय कम्पनियोंको अपनी आय बनाये रखने, ऑपरेटिंग सिस्टम (विंडोज, ऐप्पल आईओएस, एंड्रॉइड) और विकासके लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चरतक पहुंचके लिए अमेरिकी व्यवसायकी आवश्यकता है।

पिछले कुछ वर्षोंमें, भारतीय इंजीनियरोंने अपने फायदे स्पष्ट रूपसे प्रदर्शित किये हैं, जैसे कि बड़ी संख्यामें उनकी उपलब्धता, जो कम्पनियोंको अपना आकार बढ़ानेमें सहायक है, अंग्रेजी भाषाका ज्ञान, विभिन्न कार्य वातावरणोंमें अनुकूलनशीलता और समस्या-समाधानका दृष्टिकोण। आउटसोर्सिंग व्यवसायके अलावा, सिलिकॉन वैलीका प्रौद्योगिकी पावरहाउस काफी हदतक भारत एवं अन्य आप्रवासियोंकी प्रतिभाओंसे चलाया जाता है। अमेरिकी विश्वविद्यालयोंसे लेकर प्रौद्योगिकी उद्योगतक, प्रतिभाका स्रोत इन्हीं छात्रोंसे भरा हुआ है। सिलिकॉन वैलीमें दर्जनों नवाचार भारतीय मूलके उद्यमियों द्वारा स्थापित या संचालित किये जा रहे हैं। बाजारका तर्क सरल है। तकनीकी व्यवसाय प्रतिभापर निर्भर होते हैं। यदि वीजा प्रतिबंध उन्हें अमेरिकामें भारतीय इंजीनियरोंको नियुक्त करनेकी अनुमति नहीं देंगे तो वे उनमेंसे अधिकको भारतमें नियुक्त करेंगे। लिहाजा भारतसे संचालित होने वाले जीसीसीकी संख्या बढ़ेगी। यदि अमेरिकाके अलावा अन्य बाजारोंमें अवसर पैदा होंगे तो भारतीय कार्यबल उसका लाभ उठायेगा। वे भारतमें रह सकते हैं और जो अमेरिकामें हैं, वे वापस लौट सकते हैं। यदि भारत में उनके लिए चुनौतीपूर्ण और आकर्षक अवसर पैदा होते हैं। सवाल है कि क्या भारतीय कम्पनियां पश्चिमी बाजारोंपर इतनी ही निर्भर बनी रहेंगी। भारतीय कम्पनियोंने शुरुआत सेवा निर्यात और आउटसोर्सिंगसे की थी, क्योंकि प्रौद्योगिकी उत्पादों और सेवाओंके लिए कोई घरेलू बाजार नहीं था। न ही ऐसा कोई पारिस्थितिकी तंत्र था, जो स्थानीय प्रौद्योगिकी और उत्पाद विकासमें मददगार हो। पिछले दो दशकोंमें यह बदल गया है। नवाचारके लिए एक बड़ा स्थानीय बाजार और सहायता प्रणालियां हैं, जैसे कि उद्यम पूंजीतक पहुंच। जैसे-जैसे यह आगे बढ़ेगा और भारतीय बाजार परिपक्व होगा, आउटसोर्सिंगपर निर्भरता और इससे जुड़ी अनिश्चितताएं कम होती जायंगी। इस प्रक्रियामें, वर्षोंसे संचित आउटसोर्सिंग, उत्पाद विकास, आईपी निर्माण और अनुसंधानका अनुभव काम आयेगा। भारत इस संक्रमण कालसे गुजर रहा है।

# चिकित्सा क्षेत्रमें बाजारीकरण

**भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र पिछले चार दशकोंमें बने नैतिक संकटका सामना कर रहा है। इसकी शुरुआत अस्पताल क्षेत्रमें कारपोरेट घरानोंके प्रवेशसे हुई और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, वेंचर कैपिटल एवं निजी निवेशसे इसने रफ्तार पकड़ी।**

❐ चंद्रकांत

भारतीय निजी स्वास्थ्य सेवाके विकासने ऐसी व्यवस्थाएं बनायी हैं, जिनमें डाक्टरोंसे अस्पतालों, दवा कम्पनियों और संबंधित हितधारकोंके लिए मुनाफा कमानेकी अपेक्षा की जाती है। उपचार निर्णय, जो कि रोगीकी जरूरतसे निर्धारित होना चाहिए, उसपर व्यावसायिक प्रोत्साहनों और चिकित्साकरणका प्रभाव हावी हो गया है। इस परिवर्तनने डाक्टर-रोगी संबंधको बदल डाला। चिकित्सक अब मात्र स्वतंत्र पेशेवर नहीं रह गया जो रोगीके प्रति जवाबदेह हो। कई डाक्टर नैतिक बने हुए हैं और कई कारपोरेट अस्पताल भी उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहे हैं, तथापि प्रोत्साहन रूपी लालच पेशेवर आजादी कायम रखना मुश्किल कर देता है। मसलन कारपोरेट अस्पतालोंमें डाक्टरोंको वेतन तो मिलता है, लेकिन मालिकोंकी अपेक्षा होती है कि वे अधिकाधिक कमाई कर दिखायें, रोगी संख्या बढ़ायें, जांच, भर्ती और इलाज प्रक्रियाओंमें अधिक मुनाफा बनवायें। भारतमें स्वास्थ्य सेवाके कारपोरेटीकरणपर एक शोधमें उपार्जन लक्ष्य, डाक्टरी सलाहको अस्पताल भर्तीमें परिवर्तित करने या एक-दो दिन वाले इलाजको लम्बा खींचनेको दबाव बनाने और घटती स्वायत्तताको दर्ज किया है। ऐसे रंग-ढंगने अच्छे डाक्टरकी परिभाषा बदल दी है। जो चिकित्सक मरीजोंको नेक डाक्टरी सलाह देते हैं, बीमारीपर सावधानीभरा इंतजार करनेकी सलाह देते हैं या किसी महंगी प्रक्रियासे बचनेकी सलाह देते हैं, वे अधिक टेस्ट और उपचार करवाने वाले डाक्टरकी तुलनामें कम पैसा कमाते हैं। एक बार जब व्यावसायिक उत्पादकता कार्य क्षमताका पैमाना बन जाय तो नेक इरादे वाले डाक्टर भी मरीजोंके हितोंके विपरीत प्रोत्साहनोंके लालचमें फंस सकते हैं। कई चिकित्सकोंका इलाजके दाम तय करने, बिल बनाने या व्यावसायिक रणनीतिपर दखल नगण्य होता है, इसलिए विशेषज्ञता तो है लेकिन घटती स्वायत्तताके साथ।

दवा उत्पादन उद्योगमें भी इसी किस्मकी चिन्ताएं उपजी हैं। कम्पनियां उत्तरोतर ऐसी रणनीतियों अपना रही हैं जिनसे बाजारीकरण और नेक चिकित्सा शिक्षाके बीच भेद करना मुश्किल हो रहा है। सम्मेलन, सलाहकार बोर्ड, वक्ता कार्यक्रम और आतिथ्य सत्कार जैसे तरीकोंने इस लकीरको धुंधला कर रखा है। दवा उत्पादकोंके लिए बिक्री संबंधी संहितामें उपहार, यात्रा और आतिथ्य सत्कार जैसी सुविधाओंसे डाक्टरोंको प्रभावित करने संबंधी निर्देश हैं, फिर भी यह गोरखधंधा सूक्ष्म तरीकोंसे काम करता है। अस्पतालकी निजी दवा विक्रेता दुकानें इस इकोसिस्टमका उदाहरण हैं। कई अस्पताल चुनिंदा ब्रांडोंसे भरी आंतरिक फार्मेसियां संचालित करते हैं, डाक्टरोंको वहां रखी दवाएं ही लिखनेको कहा जाता है। इससे मरीजका क्रय चयन सीमित हो जाता है और हॉस्पिटलकी कमाई बढ़ जाती है। पिछले १८ महीनोंमें मोटापा कम करने वाली दवाओंकी बढ़ती मांग इस तनावको दिखाती है। जीएलपी-१ रिसेप्टर एगोनिस्ट और उनसे जुड़ी दवाओंका फायदा सहीमें चुने गये मरीजको हो सकता है। फिर भी, सम्मेलनों और मेडिकल प्रचार शिविरोंके जरिये की जाती इनकी आक्रामक मार्केटिंगपर सोचना जरूरी है। एक मेडिकल विशेषज्ञ ब्रांड एंबेसडर बननेकी बजाय सुबूतोंको समझने और व्याख्या करने वाला हो। उनकी भूमिका केवल यह बताना नहीं है कि दवा क्या कर सकती है, बल्कि यह बताना भी है कि किसे इसकी जरूरत नहीं है, क्या अनिश्चितताएं हैं, क्या-क्या बुरे असर और लागत है, कितने समयतक वास्तवमें इलाजकी जरूरत है और दवाके बिना कौनसे उपचार ढंगका महत्व कायम है। कारपोरेट स्वास्थ्य क्षेत्रमें दवाएं तेजीसे मुख्य भूमिकामें आ रही हैं। ये चिन्ताएं लम्बे समयसे चली आ रही हैं। २०१८ में समीरन नंदी, केशव देशिराजु और संजय नागरालने स्वास्थ्य सेवा रक्षक या भक्षक। भारतमें स्वास्थ्य सेवाओंमें भ्रष्टाचार नामक पुस्तक संपादितकी थी। इसमें हितोंका टकराव, कारपोरेट अस्पतालोंके तौर-तरीके, दवा उत्पादक कम्पनियोंका प्रभाव, मेडिकल नियमन और व्यावसायिक नैतिकताकी जांच की गयी थी। आज भी इसकी प्रासंगिकता चिन्ताजनक है। चिकित्सा जगतने बार-बार इस समस्याकी शिनाख्त तो की, लेकिन सुधार सीमित ही रहा।

कमजोर नियमन मुख्य समस्या है। भारतमें डाक्टरोंके लिए नैतिकता संहिता और दवा उत्पादनकी मार्केटिंगका नियंत्रण करने वाले नियम हैं। रेफरल कमीशन, गलत प्रोत्साहन और व्यापारिक प्रभावोंके नाना तरीकोंपर रोक है। फिर भी, क्रियान्वयन एक समान नहीं और अक्सर काररवाई शिकायतों या घोटालोंके बाद होती है, न कि व्यवस्थित निगरानीके जरिये। जब क्रियान्वन ही अनिश्चित हो तो नैतिक संहिताका कोई खास मतलब नहीं। फिर भी, भारतमें हम दिखावेपर ज्यादा ध्यान देते हैं। २०२२ में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोगने मेडिकल पढ़ाई शुरू करने वाले छात्रोंके लिए नयी चरक शपथकी सिफारिश की। मकसद इसे नये चिकित्सकोंको ऐतिहासिक रूपसे दिलायी जाने वाली हिप्पोक्रेटिक शपथकी जगह लेना था। हालांकि दोनों सेवा एवं मरीजकी भलाईको चिकित्सा पेशेके केन्द्रमें रखती हैं। परन्तु शपथ तब दिखावा बनकर रह जाती है जब युवा डाक्टर ऐसी जगह ट्रेनिंग लेते हों जहां व्यापारिक ध्येय, हितोंका टकराव और गैर-जरूरी दखलका सामान्यीकरण हो चुका है। शपथसे ज्यादा अहम है कि क्या संस्थान चिकित्सकको सिद्धांतोंके अनुसार इलाज करने देते हैं। अन्य घटनाओंने भी इन दबावोंको बढ़ाया। देशमें विशेषज्ञता वाली चिकित्सा शिक्षा तेजीसे बढ़नेके मद्देनजर भारत खुदको मेडिकल टूरिज्मके मुकामके तौरपर रख रहा है। दोनोंके फायदे हैं, लेकिन इनसे अस्पताल नेटवर्ककी आर्थिक ताकत ज्यादा मजबूत हो सकती है। विशेषज्ञता वाले डाक्टर आधारभूत ढांचा, रोग पहचान तंत्र, मरीज प्रवाह और अपनी व्यावसायिक पहचानके लिए संस्थानोंपर निर्भर हो रहे हैं, जिससे क्लिनिक आधारित इलाजसे कमाईकी ताकत घट रही है।

मकसद पुराने दौरको बढ़िया बताकर पेश करना नहीं। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमें सदा ही धन, पदानुक्रम और हितोंका टकराव बना रहा है। न ही कारपोरेट अस्पताल और न ही दवा उत्पादक कम्पनियां अपने आपमें अनैतिक होती हैं। चिन्ता यह है कि स्वास्थ्य सेवाका मतलब अब ज्यादातर दवाएं, टेस्ट, सप्लीमेंट्स, प्रोसीजर और ज्यादा खर्च बन गया है। डाक्टर ऐसी चीजें सही ठहराने लगे हैं जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं और मरीजोंको ऐसे इलाज भुगतने पड़ते हैं। अनिवार्य प्रश्न है कि क्या व्यापारिक लाभ चिकित्सकीय निर्णयोंके अधीन बने रहें या उनपर हावी होते जायं। चिकित्साका वजूद सर्वप्रथम मरीजके हितमें हो। पेशेवर आजादी, सही इलाज और जनताके भरोसेके लिए इस सिद्धांतको बनाये रखना जरूरी है। जब मरीजोंको शक हो जाय कि परीक्षणों, दवाकी पर्ची, इलाज प्रक्रियामें किसी औरके पास भेजने या उपचार क्रियाके पीछे छिपे आर्थिक मकसद हैं तो डाक्टरोंकी नैतिक साख कमजोर होती है और स्वास्थ्य देखभाल व्यापार बन जाता है। भारतीय चिकित्साके सामने संकट सिर्फ इलाजपर खर्चकी मात्राका नहीं, बल्कि इसका है कि चिकित्साका स्वरूप क्यासे क्या बनता जा रहा। भारतको एक ऐसे आधुनिक स्वास्थ्य तंत्रकी जरूरत है जिसमें पूंजी इलाज करनेमें लगे, तकनीक उपचारमें फैसले लेनेमें सहायक हो और संस्थान पेशेवर नैतिकतासे समझौता करनेके बजाय उसकी रक्षा करें। शपथका महत्व तभी होता है जब व्यवस्था उसे निभानेका मौका दे।




## संस्कार

❐ अनुज आचार्य

संस्कार, संस्कृति और सभ्यता जीवनके तीन महत्वपूर्ण आधार हैं। संस्कार व्यक्तिको भीतरसे गढ़ते हैं, संस्कृति चेतनाको समाजतक पहुंचाती है और सभ्यता सामूहिक जीवनका बाहरी स्वरूप निर्मित करती है। संस्कारका मूल भाव है-मन, वचन और कर्मका परिष्कार। जब बालक अपने माता-पिता और गुरुजनोंका सम्मान करना सीखता है, सत्य बोलनेका प्रयास करता है, जरूरतमंदकी सहायता करता है, प्रकृतिके प्रति संवेदना रखता है और अपने कर्तव्यको ईमानदारीसे निभाता है, तब उसके भीतर संस्कारोंका निर्माण होता है। संस्कारकी सबसे बड़ी परीक्षा उस समय होती है जब व्यक्तिको देखने वाला कोई नहीं होता, फिर भी वह गलत रास्तेपर जानेसे स्वयंको रोक लेता है। यही भीतरकी जागरूकता संस्कारको केवल शिक्षासे अलग करके जीवन-मूल्य बनाती है। संस्कार जब व्यक्तिकी सीमाओंसे निकलकर परिवार, समाज और पीढ़ियोंके जीवनमें प्रवाहित होते हैं, तब संस्कृतिका निर्माण होता है। हमारी भाषा, साहित्य, लोकगीत, संगीत, कला, पर्व-उत्सव, पारिवारिक परम्पराएं, प्रकृतिके प्रति दृष्टिकोण, अतिथि-सत्कार, सह-अस्तित्व और आध्यात्मिक चिंतन- ये सभी संस्कृतिके व्यापक स्वरूपको व्यक्त करते हैं। इसलिए संस्कृति किसी समाजकी केवल पहचान नहीं, उसकी सामूहिक चेतना भी है। भारतीय संस्कृतिकी विशेषता रही है कि उसने जीवनको भौतिक उपलब्धियोंके साथ नैतिक और आध्यात्मिक मूल्योंसे जोड़कर देखा। वसुधैव कुटुम्बकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः और प्रकृतिके प्रति सम्मान जैसे विचार मनुष्यको केवल अपने हिततक सीमित नहीं रखते, बल्कि उसे व्यापक जीवन-जगतसे जोड़ते हैं। यही कारण है कि भारतीय संस्कृतिमें धर्मका अर्थ केवल पूजा-पद्धति नहीं, बल्कि कर्तव्य, सदाचार और लोकमंगलकी भावनासे भी जुड़ा रहा है। सभ्यताका संबंध मुख्यतः मनुष्यकी बाहरी और संस्थागत प्रगतिसे है। विज्ञान, तकनीक, परिवहन, संचार, भवन, सड़कें प्रशासन और आधुनिक संस्थाएं सभ्यताकी उपलब्धियोंको दर्शाती हैं। सभ्यता जीवनको सुविधाजनक बनाती है, लेकिन संस्कृति यह निर्धारित करती है कि उन सुविधाओंका उपयोग किस मानवीय उद्देश्यके लिए किया जाय। अत्याधुनिक साधन मनुष्यके हाथोंमें हों, लेकिन संवेदना और विवेकका अभाव हो तो विकास अधूरा रह जाता है। इसके विपरीत संस्कार और संस्कृतिसे जुड़ी आधुनिकता मानव कल्याणका प्रभावी माध्यम बन सकती है। संस्कार बीज हैं, संस्कृति उसका विकसित वृक्ष और सभ्यता उस